Utlisation of Funds ARWSP

6534. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the benefits under the Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) fund have been fully utilised by the persons belonging to Scheduled Castes/Tribes during the last three years;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) The funds under Accelerated Rural Water Supply Programme are not released to the individuals directly by the Central Government but to the State Government for implementation of Rural Water Supply Schemes. However, 25% and 10% of the funds are to be utilised by the State Government for providing drinking water facilites for Scheduled Castes & Scheduled Tribes population in rural areas respectively.

(b) and (c) About 73% SC and 89.5% of ST population have been provided with safe drinking water facilities so far.

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना

6535. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों, विशेषकर कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन करने हेतु अन्य संबंधित विभागों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक विभाग की क्या-क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) से (घ) जहां तक ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का संबंध है, मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों अथवा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। लेकिन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर पर ढांचा निधियों के 10% का समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाभार्थियों के लिए ढांचा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने और उनमें सुधार करने हेतु उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। तथापि उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामोद्योग विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी। उस मंत्रालय ने भी सूचित किया है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों, विशेष रूप से कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा सुविधाएं देने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। तथापि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशेड स्थापित करने के लिए सहायता देता है। इसके अतिरिक्त खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 10 उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा, 22 विभागीय और 21 गैर-विभागीय बहु आयामी प्रशिक्षण केन्द्रों की मार्फत कारीगरों और पर्यवेक्षक स्तर के तकनीकी कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत गुजरात को आवंटित की गई धनराशि

6536. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात को जिले-वार रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और तत्कालीन सरकार द्वारा वास्तविक रूप से कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई;

(ख) क्या सरकार ने धनराशि के वास्तविक उपयोग की समीक्षा की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं और उस संबंध में क्या त्रुटियां समाने आई हैं; और

(ग) क्या सरकार वर्ष 1995-96 के लिए धनराशि आवंटित करते समय बढ़िया कार्य निष्पादन करने वाले जिलों को महत्व देने का विचार रखती है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत रिलीज की गयी केन्द्रीय सहायता के जिलावार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण दिया गया है। **(नीचे देखिए)** निधियों के इस्तेमाल के जिलावार ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राज्य से 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान क्रमशः 146.21 लाख रुपये एवं 1014.82 लाख रुपये के इस्तेमाल की सूचना मिली है।

(ख) सुनिश्चित रोजगार योजना की समीक्षा राज्य सरकार से प्राप्त मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। प्राप्त सूचना के अनुसार 1993-94 के दौरान 71 कार्य पूरे कर दिये गये तथा अन्य 119 कार्य प्रगति पर थे। 1994-95 के दौरान 327 कार्य पूरे कर दिये सूचित किए गए थे तथा अन्य 1531 कार्य प्रगति पर थे। 1993-94 के दौरान रोजगार के 6.75 लाख श्रमदिन सृजित किये गये जबकि 1994-95 के दौरान रोजगार के 20.25 लाख श्रमदिन सृजित किये गये। किसी गंभीर कमी का पता नहीं लगा।

(ग) चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जिलों को निधियों की रिलीज पहले से दी गयी निधियों के इस्तेमाल की प्रगति एवं श्रमदिनों की उपस्थिति के आधार पर की जाती है इसलिए बेहतर निष्पादन दर्शाने वाले जिलों को खराब निष्पादन दर्शाने वाले जिलों की तुलना में अधिक निधियां मुहैया करायी जाती है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं॰	जिला	1993-94	1994-95
1	2	3	4
1.	जामनगर	10.00	250.00
2.	राजकोट	25.00	280.00
3.	सुरेन्द्रनगर	45.00	360.00
4.	भाव नगर	15.00	210.00
5.	अमरेली	40.00	190.00
6.	जूनागढ़	0.00	210.00
7.	कच्छ	35.00	200.00
8.	बनासकांठा	45.00	80.00
9.	सबरकांठा	25.00	130.00
10.	मेहसाना	10.00	40.00
11.	अहमदाबाद	10.00	40.00
12.	पंचमहल	55.00	440.00
13.	बड़ोदरा	25.00	160.00
14.	भड़ौच	35.00	260.00
15.	सूरत	65.00	260.00

1	2	3	4
16.	वलसाड	40.00	320.00
17.	डांग्स	5.00	50.00
	कुल :	485.00	3580.00

रोजगार आश्वासन योजना

6537. श्री राम जेठमलानी:
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कतिपय क्षेत्रों में रोजगार आश्वासन योजना प्रारंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अभी तक कुल कितने लोगों को रोजगार दिये गए हैं;

(ग) किन-किन राज्यों के कितने-कितने प्रखण्डों में यह योजना अब-तक चालू की जा चुकी है और कितने ऐसे शेष प्रखण्डों की पहचान की जा चुकी है जहां इस योजना को लागू किए जाने का विचार है;

(घ) क्या इस योजना का विस्तार करने की भी कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो देश के समस्त पिछड़े और निर्धन प्रखण्डों में कब तक इस योजना को लागू करने का लक्ष्य है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) जी हां, सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्टूबर, 1993 से सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (गोवा, पंजाब, दिल्ली चंडीगढ़ और पांडिचेरी को छोड़कर) में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) केन्द्र द्वारा योजना के अंतर्गत प्रगति पूरे किए गए कार्यों की संख्या और सृजित श्रमदिनों की संख्या के आधार पर निगरानी की जा रही है। योजना के शुरू होने से लेकर अब तक कुल 1,11,958 कार्यों को पूरा किया गया है जिनसे 2,915 लाख श्रमदिनों का सृजन हुआ।

(ग) प्रत्येक राज्य, जिसमें योजना कार्यान्वित की जा रही है, में खण्डों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1995-96 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कवर किए गए खण्डों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सुनिश्चित रोजगार योजना खण्डों का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	155
2.	अरुणाचल प्रदेश	56
3.	असम	142
4.	बिहार	266
5.	गुजरात	137
6.	हरियाणा	44
7.	हिमाचल प्रदेश	18
8.	जम्मू व कश्मीर	80
9.	कर्नाटक	119
10.	केरल	21
11.	मध्य प्रदेश	297
12.	महाराष्ट्र	173
13.	मणीपुर	22
14.	मेघालय	32
15.	मिजोरम	20
16.	नागालैंड	28
17.	उड़ीसा	175
18.	राजस्थान	172
19.	सिक्किम	4
20.	तमिलनाडु	89
21.	त्रिपुरा	18
22.	उत्तर प्रदेश	248